माननीय एम.एम कुमार और जियेंद्र चौहान, जे.जे. के समक्ष

अनिल सागर-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की

संख्या 13811

19 अगस्त 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226–हरियाणा पब्लिक निर्माण विभाग (भवन और सड़क शाखा) अनुसंधान प्रयोगशाला (समूह बी) सेवा नियम, 1996-नियम 7-प्रतिवादी संख्या 4 को सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर पदोन्नति-प्रतिवादी के पास आर1.7 के तहत अपेक्षित आवश्यक योग्यता नहीं है- योग्यता पूरी करने की आवश्यकता अनिवार्य है न कि केवल निर्देशिका - नियम 17 के तहत 'आवश्यकता' या 'आवश्यकता' के मामले में छूट दी जा सकती है - याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त योग्यता और अनुभव है - न तो अस्तित्व में कोई 'आवश्यकता' है और न ही इसमें छूट देना समीचीन होगा योग्यता क्योंकि उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त के रूप में उम्मीदवार के पास शैक्षणिक योग्यता होनी आवश्यक है - याचिका स्वीकार की गई।

निर्धारित, *नियम 7 की भाषा इस अभिव्यक्ति से शुरू होती है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास योग्यता और अनुभव न हो। इससे पता चलता है कि योग्यता पूरी करने की आवश्यकता अनिवार्य है न कि केवल निर्देशिका। प्रतिवादी नंबर 4 के पास एमएससी या बैचलर ऑफ इंजीनियर या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की आवश्यक योग्यता नहीं है। वह सिर्फ बी.एससी. है जबकि याचिकाकर्ता ने ए.एम.आई.ई. की डिग्री हासिल की है। जो सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर पदोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त और समकक्ष डिग्री है। नियम 7 की आवश्यकता अनिवार्य है और नियमों के नियम 17 के तहत 'आवश्यकता' या 'उपयुक्तता' के मामले में छूट दी जा सकती है। न तो इसकी कोई आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त योग्यता और अनुभव उपलब्ध है और न ही योग्यता में छूट देना समीचीन होगा क्योंकि उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त के रूप में उम्मीदवार के पास शैक्षिक योग्यता होना आवश्यक है।*

(पैरा 12 *और* 13)

याचिकाकर्ता के वकील एस.के. सूद।
हरीश राठी, सीनियर डीएजी हरियाणा।
आर.एस. मामली, प्रतिवादी संख्या 4 के वकील।
सुश्री मिनाक्षी, प्रतिवादी संख्या 5 की वकील।

एम. एम. कुमार, जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में निदेशक-सह-अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान प्रयोगशाला के कार्यालय में अनुसंधान सहायक के पद से सहायक निदेशक के पद पर प्रतिवादी

संख्या 4 जयबीर सिंह की पदोन्नति को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। पी.डब्लू.डी. बी एंड आर शाखा, हिसार। याचिका के समर्थन में मुख्य आधार यह है कि प्रतिवादी नंबर 4 को इस तथ्य के बावजूद पदोन्नति दी गई है कि वह हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क शाखा) अनुसंधान प्रयोगशाला (समूह बी) के नियम 7 के अनुसार योग्य नहीं था। सेवा नियम, 1996 (संक्षिप्तता के लिए 'नियम') और नियमों के नियम 17 द्वारा दी गई छूट की शक्ति का प्रयोग तब नहीं किया जा सकता जब याचिकाकर्ता जैसा व्यक्ति जो पूरी तरह से योग्य हो, उपलब्ध हो।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 20 जून 1987 से अनुसंधान सहायता के पद पर कार्यरत है। उनकी नियुक्ति प्रारंभ में कार्य प्रभार के आधार पर थी जो निर्बाध और बिना किसी ब्रेक के थी। उनकी सेवाओं को 1 अप्रैल, 1993 से नियमित कर दिया गया था। नियमों के अनुसार, अनुसंधान सहायक का पद सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर पदोन्नति के लिए एक फीडर पद है जो नियमों द्वारा शासित होता है। नियमावली का नियम 7 पदोन्नति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि परिशिष्ट 'बी' में, जिसे नियमों के नियम 7 में संदर्भित किया गया है, सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव यह है कि एक व्यक्ति के पास एम. एससी./ होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट के रूप में पांच साल के अनुभव के साथ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समकक्ष डिग्री। आगे यह भी कहा गया है कि 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने की आवश्यकता है जबकि अन्य पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। नियमों के नियम 17 के अनुसार, सरकार को किसी भी वर्ग या

श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति प्राप्त है।

(3) एक जगदेव सिंह जो सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे, सेवानिवृत्त हो गए और पदोन्नति द्वारा भरा जाने वाला पद रिक्त हो गया। यह दावा किया गया है कि केवल याचिकाकर्ता ही अनुसंधान सहायक में से सहायक निदेशक के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवार था क्योंकि उसने एएमआईई की योग्यता हासिल कर ली थी। तदनुसार, 24 नवंबर, 2005 को निदेशक-सह-अधीक्षण अभियंता द्वारा पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई थी। उपर्युक्त सिफारिश से पता चलता है कि वरिष्ठता सूची के अनुसार जैसा कि 1 जून, 1999 को था; 12 अनुसंधान सहायक थे। यह स्पष्ट किया गया कि क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10 पर अनुसंधान सहायक नियमों और 13 नवंबर, 2005 के पत्र के अनुसार अपेक्षित योग्यता पूरी नहीं करते थे। क्रम संख्या पर केवल दो अनुसंधान सहायक 8 एवं 11 सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विचाराधीन थे एवं उनका विवरण भेजा गया था। वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 11 पर याचिकाकर्ता का नाम था और सिफारिशों में निम्नलिखित विवरण शामिल थे:

" 1. वरिष्ठता सूची में क्रमांक 11

2. नाम: अनिल सागर

3. जन्मतिथि: 26 जुलाई, 1963

4. योग्यताएँ:

(i) 1983 में हरियाणा पॉलिटेक्निक, नीलोखेड़ी से प्रथम श्रेणी

में सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया।

(ii) एएमआईई (सिविल इंजीनियरिंग) ए और एएमआईई (सिविल इंजीनियरिंग) की धारा 6 (जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बराबर है) क्रमशः 1987 की गर्मियों और 1990 की गर्मियों में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) 8 गोखले से रोड, कलकत्ता.

5. पोस्टिंग का स्थान: कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय डिवीजन, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर शाखा, पानीपत (कमल सर्कल)

6. अनुभव: 25-6-1987 से 31-3-1993 (डब्ल्यूसी) + 1-4-1993 से आगे तक नियमित आधार पर।

उपरोक्त विवरण से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री अनिल सागर, अनुसंधान सहायक आपके पत्र संख्या 568/ई-एल 11/72/11625/ ईIII, दिनांक 13 जुलाई, 2005 के अनुसार वांछित योग्यता और अनुभव के संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सेवा नियम, अनुसंधान प्रयोगशाला। ग्रुप बी, अक्टूबर 1,1996। श्री अनिल सागर, अनुसंधान सहायक की योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उनके नाम को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए दृढ़ता से अनुशंसित किया जाता है|

(4) इसी प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती का नाम। वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 8 पर रहीं उर्मिला गर्ग की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के साथ भेजा गया उनका विस्तृत विवरण भी नीचे देखा गया है:

" 1. वरिष्ठता सूची में क्रमांक 8

2. नाम:उर्मिला गर्ग

3. जन्मतिथि: 1-10-1953

4. योग्यताएं: (i) बी.एससी. भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ

5. पोस्टिंग का स्थान: सहायक निदेशक, अनुसंधान प्रयोगशाला। भिवानी

6. अनुभव: 31-3-1979 से 31-12-1986 (डब्ल्यूसी) +1-1-

1987 से आगे तक नियमित आधार पर।

श्रीमती उर्मिला गर्ग गणित में एम.एससी हैं। आपके दयालु निर्णय के लिए उनका नाम भी भेजा जा रहा है।

आगे कहा गया है कि सर्विस रूल्स रिसर्च लैब के अनुसार। ग्रुप बी. 1 अक्टूबर 1996:

सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो:

1. प्रथम श्रेणी एम.एससी. भौतिकी या रसायन विज्ञान में

   या

   प्रथम श्रेणी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो:

   मास्टर ऑफ साइंस/बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समकक्ष के साथ रिसर्च असिस्टेंट के रूप में 5 साल का अनुभव।

   त्वरित संदर्भ के लिए सेवा नियमों की एक फोटो स्टेट प्रति भी संलग्न है। दोनों अनुसंधान सहायकों के प्रमाणपत्रों की फोटो स्टेट सत्यापित प्रतियां आपके कार्यालय में जमा की जाएंगी - इस कार्यालय संख्या 293, दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 के तहत।

(5) निदेशक - प्रतिवादी संख्या 3 ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश नहीं की, हालांकि वे याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे क्योंकि वे योग्यता पूरी नहीं

करते थे। याचिकाकर्ता ने 24 अगस्त, 2005, 5 मई, 2006, 6 नवंबर, 2006, 24 अप्रैल, 2007 और 28 जून, 2007 को विभिन्न अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी 5 से पी 9) भेजकर उत्तरदाताओं से अनुरोध किया कि वे पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार करें। सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) का पद। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि 28 जुलाई, 1990 को जब पद खाली था तब श्री जगदेव सिंह को सहायक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था, जो अकेले ही योग्यताएं पूरी करते थे और अपने वरिष्ठ श्री पीसी के रूप में पदोन्नति के पात्र थे। जो मित्तल योग्य नहीं थे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। हालाँकि, इस बार प्रतिवादी संख्या जयबीर सिंह को पदोन्नति देकर याचिकाकर्ता जो पूरी तरह से योग्य है, को नजरअंदाज कर दिया गया है। 4 उसे नियमों के नियम 17 के तहत छूट प्रदान करके, जैसा कि 31 जुलाई, 2007 के आदेश (अनुलग्नक पी 10) के अवलोकन से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में छूट की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, खासकर जब यह किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में न हो।

(6) उनके द्वारा दायर लिखित बयान में आधिकारिक उत्तरदाताओं का रुख यह है कि प्रतिवादी नंबर 4 बीएससी डिग्री के साथ योग्य है और वरिष्ठतम सहायक रहा है। बताया गया है कि उनके पास रिसर्च असिस्टेंट के रूप में 29 साल का अनुभव है। यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता 1 अप्रैल, 1993 से या नियमित आधार पर काम कर रहा है और उसके पास एएमआईई की योग्यता है। आगे यह भी दावा किया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति ने 20 अप्रैल, 2007 को हुई अपनी बैठक में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर पदोन्नति के लिए प्रतिवादी नंबर 4 जयबीर सिंह के नाम पर विचार किया कि सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार सेवानिवृत्त हो गया है। और अन्य उम्मीदवारों के पास आवश्यक योग्यता यानी एम.एससी. नहीं थी। सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु। प्रतिवादी संख्या 4 को वरिष्ठतम होने के कारण पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना गया क्योंकि याचिकाकर्ता से वरिष्ठ आठ व्यक्तियों की

अनदेखी करना विभाग के कामकाज के लिए अनुकूल नहीं माना गया क्योंकि याचिकाकर्ता वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 11 पर था, हालांकि उसके पास योग्यता थी। एएमआईई का. इसलिए, विभागीय पदोन्नति समिति ने सिफारिश की कि सरकार नियमों के नियम 17 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 4 जयबीर सिंह के मामले में योग्यता में छूट पर विचार कर सकती है। तदनुसार समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उनके मामले में शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है। इन्हीं परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 4 की पदोन्नति का आदेश दिया गया है।

(7) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर अपने अलग लिखित बयान में छूट को उचित ठहराया गया है और एक बिल्कुल अलग रुख अपनाया गया है कि सड़क के नमूने के परीक्षण के लिए एक अलग कैडर बनाया गया था। उत्तर के पैरा 2 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता सहायक निदेशक की पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता का कैडर प्रतिवादी क्रमांक 4 से भिन्न है क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 4 को प्रयोगशाला में विशेष कार्य के लिए सीधे भर्ती किया गया था और वह है इस प्रकार एक अलग कैडर है जबकि याचिकाकर्ता को शुरू में कार्य प्रभार के आधार पर भर्ती किया गया था और उसके बाद नियमित कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 को प्रयोगशाला में विशेष प्रकार का अनुभव है और इसलिए उसके मामले में विशेष संवर्ग में छूट दी गई है।

(8) पार्टियों के वकील को सुनने के बाद, हमारा मानना है कि प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति नियमों का घोर उल्लंघन करके की गई है। संदर्भ की सुविधा के लिए नियमों के नियम 7 को परिशिष्ट के साथ यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"7. किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास सीधी भर्ती के मामले में इन नियमों के परिशिष्ट बी के कॉलम 2 में निर्दिष्ट योग्यताएं और अनुभव

न हों और उपरोक्त परिशिष्ट के मामले में उपरोक्त परिशिष्ट के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यताएं और अनुभव न हों। सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति:

बशर्ते कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व से संबंधित पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित योग्यता आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी के विवेक के आधार पर 50% की सीमा तक छूट दी जाएगी। -अपेक्षित अनुभव रखने वाले सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियां, लिखित में ऐसा करने का कारण दर्ज करने के बाद उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।"

परिशिष्ट 'बी' नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

पद का पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो
सहायक संचालक	प्रथम श्रेणी एम.एससी. फिजिक्स या केमिस्ट्री में या प्रथम श्रेणी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी	(i) अनुसंधान सहायक के रूप में पांच साल के अनुभव के साथ मास्टर ऑफ साइंस/बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या समकक्ष पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए। (ii) स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए मास्टर ऑफ साइंस / बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग /

		बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या अनुसंधान प्रयोगशाला में पांच साल के अनुभव के बराबर।

(9) उपर्युक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास एम.एससी. होना आवश्यक है। या बी.ई. या बी.टेक, या अनुसंधान सहायक के रूप में पांच साल के अनुभव के साथ समकक्ष योग्यता। नियम की भाषा अनिवार्य है क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने पर रोक शामिल है जब तक कि ऐसे व्यक्ति के पास परिशिष्ट "बी" में उल्लिखित योग्यता और अनुभव न हो। यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 के पास एम.एससी. की डिग्री नहीं है। हालाँकि, नियमों के नियम 17 द्वारा अपेक्षित छूट की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा 31 जुलाई, 2007 को आदेश पारित करके किया गया है।

(10) विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या नियमों के नियम 17 द्वारा अपेक्षित छूट की शक्ति का प्रयोग प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में उसे सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर नियुक्ति देकर किया जा सकता है, खासकर जब नियम 7 एक अनिवार्य भाषा में शामिल है जिसके लिए एमएससी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री की आवश्यकता होती है। यह सर्वविदित है कि अनुभव वैधानिक नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का विकल्प नहीं हो सकता। उस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य बनाम धरमबीर (1) के मामले में फैसले के पैरा 32 पर भरोसा किया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

“32. एक दशक से अधिक समय तक प्रश्नाधीन पद पर काम करने के कारण प्रतिवादी द्वारा प्राप्त "अनुभव" को उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त के रूप में उम्मीदवार द्वारा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के साथ नहीं

जोड़ा जा सकता है। यदि सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ पद सृजित किए हैं, तो नियुक्ति का तरीका या योग्यताएं निर्धारित करना उसका काम है जो उन पदों पर नियुक्त होने से पहले उम्मीदवारों के पास होनी चाहिए। योग्यताएं स्वाभाविक रूप से पदों की प्रकृति या सरकार द्वारा बनाई गई सेवा के साथ भिन्न होंगी।"

(11) यह भी समान रूप से स्थापित है कि उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए किसी व्यक्ति के पास आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता के अभाव में उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। उस संबंध में डॉ. **भानु प्रसाद पांडा बनाम चांसलर, संबलपुर विश्वविद्यालय और अन्य** (2) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है हमारा यह भी मानना है कि एक बार अपेक्षित योग्यता वाला व्यक्ति पदोन्नति पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यताएं पूरी करने पर किसी व्यक्ति के मामले में छूट की शक्ति का सहारा लेना अस्वीकार्य होगा। **प्रिंसिपल, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बनाम वीरेंद्र कुमार** (3) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि नियम निर्देशिका है तो छूट दी जा सकती है और वह भी परिभाषित और वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देशों द्वारा शासित होनी चाहिए। उपर्युक्त टिप्पणियाँ फैसले के पैरा 16 में की गई हैं जो इस प्रकार है:

"16. क्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश में निहित नियम अनिवार्य हैं या निर्देशिका एक ऐसा मामला है जिस पर विश्वविद्यालय को आवश्यकता की प्रकृति, उसके उद्देश्य जैसे सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद विचार करना होगा और शैक्षिक उत्कृष्टता पर इसकी छूट के परिणाम। हम उस प्रश्न पर नहीं गए हैं क्योंकि उस संबंध में हमारे समक्ष या उच्च न्यायालय में कोई विवाद नहीं किया गया था। हालाँकि, एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि विश्वविद्यालय मानता है कि कोई प्रावधान अनिवार्य नहीं है, तो विशेष मामलों में उसकी छूट को वस्तुनिष्ठ विचारों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण, यहां तक कि कोई

विश्वविद्यालय, जिसे छात्र समुदाय के भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है, नियमों में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का चयन नहीं कर सकता है। सबसे पहले, किसी नियम की कठोरता में ढील दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी छूट नियमों के तहत स्वीकार्य हो या यदि नियम निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। दूसरे, भले ही किसी नियम में ढील देने की अनुमति हो, ऐसी छूट, जैसा कि ऊपर कहा गया है, परिभाषित दिशानिर्देशों द्वारा शासित होनी चाहिए।"

(12) वर्तमान मामले में नियम 7 की भाषा इस अभिव्यक्ति से शुरू होती है कि 'किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास योग्यता और अनुभव न हो।' इससे पता चलता है कि योग्यता पूरी करने की आवश्यकता अनिवार्य है न कि केवल निर्देशिका। डॉ. वीरेंद्र कुमार के मामले (सुप्रा) में एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सवाल खड़ा हो गया था और नियम की भाषा के अनुसार उम्मीदवार के पास एमबीबीएस की डिग्री और अन्य अनुभव होना आवश्यक था। नियम की भाषा नियमों के नियम 7 की भाषा के समान है जिसमें कहा गया है कि जिस उम्मीदवार ने प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि पर एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त नहीं की है वह पात्र नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नानुसार कहा:-

10. अध्यादेश 1 इन शब्दों से शुरू होता है: "कोई भी उम्मीदवार डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि (जोर न दिया गया हो)। प्रतिवादी को हमारे द्वारा रेखांकित शब्दों से अपने विवाद का आधार मिलता है। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि अध्यादेश 1 परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता की शर्तों को निर्धारित करता है, न कि एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए। इसलिए, पात्रता की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख परीक्षा की तारीख है, न कि आवेदन की तारीख। इस विवाद को स्वीकार करना कठिन है. अध्यादेश 1 के खंड (ए) से (ई) एक एकीकृत योजना के हिस्से हैं और इसलिए उन खंडों की व्याख्या के लिए अलग-अलग मानदंड लागू करना गलत होगा। अध्यादेश के खंड (ए) के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार ने एम.बी.बी.एस. की डिग्री "प्राप्त" की हो। यह निर्विवाद है

कि एक उम्मीदवार, जिसने अभी तक एम.बी.बी.एस की डिग्री प्राप्त नहीं की है, वह एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस प्रत्याशा में या इस अनुमान पर आवेदन कर सकता है कि वह एम.डी. परीक्षा आयोजित होने से पहले उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा। जिस तारीख को वह एम.डी. परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उस दिन उसके पास एम.बी.बी.एस की डिग्री होनी चाहिए। खंड (बी) के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार ने एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटिंग हाउसमैनशिप "पूरी" कर ली हो। जैसा कि 'खंड (ए) के मामले में है, यह योग्यता भी उम्मीदवार के पास उस तारीख को होनी चाहिए जिस दिन वह एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है। यह पर्याप्त नहीं है कि उम्मीदवार ने आवेदन करने के बाद और परीक्षा की तारीख से पहले एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटिंग हाउसमैनशिप पूरी कर ली हो। खंड (सी) की भाषा भौतिक दृष्टि से खंड (ए) और (बी) की भाषा के समान है, अध्यादेश के खंड (सी) के दूसरे परंतुक के पैराग्राफ (i) द्वारा निर्धारित समकक्षता को एक पल के लिए छोड़ दें। खंड (सी) के मूल प्रावधान के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार ने "पूर्ण पंजीकरण के बाद एक वर्ष की हाउसमैनशिप या समकक्ष नौकरी की हो"। इस खंड की व्याख्या के लिए उस परीक्षण से भिन्न परीक्षण लागू करने का कोई औचित्य नहीं है जिसे खंड (ए) और (बी) की व्याख्या के लिए लागू किया जाना है। न तो खंड (सी) की भाषा और न ही न्याय और निष्पक्ष खेल की आवश्यकता ऐसे पाठ्यक्रम की गारंटी देती है। इसलिए, सीएल द्वारा निर्धारित शर्त. (सी) यह भी दिखाया जाना चाहिए कि उम्मीदवार द्वारा एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तारीख को इसे पूरा किया गया है, बाद में नहीं। अध्यादेश का खंड (डी) इसी दिशा में इशारा करता है। इसके लिए आवश्यक है कि खंड 1 (सी) द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार ने "कॉलेज में संबंधित विभाग में विषय में दो साल का काम किया हो"। खंड (ए) से (डी) में प्रयुक्त क्रियाएँ क्रमशः: "प्राप्त किया है", "पूरा किया है", "किया है" और "डाला है"। उन शब्दों को उनका स्वाभाविक अर्थ देते हुए, हमारा विचार है कि इन सभी खंडों की आवश्यकता को उम्मीदवार को उस तिथि पर पूरा करना होगा जिस दिन वह एम.डी. या एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है। यह पर्याप्त नहीं है कि वह परीक्षा की तिथि पर इन खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करता

है। (महत्व जोड़ें)

(13) जब वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच उनके आधिपत्य द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में की जाती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी नंबर 4 जयबीर सिंह के पास एमएससी या बैचलर ऑफ इंजीनियर या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की आवश्यक योग्यता नहीं है। वह सिर्फ बी.एससी. है जबकि याचिकाकर्ता ने ए.एम.आई.ई. की डिग्री हासिल की है। जो सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर पदोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त और समकक्ष डिग्री है। नियम 7 की आवश्यकता अनिवार्य है और नियमों के नियम 17 के तहत आवश्यकता या 'उपयुक्तता' के मामले में छूट दी जा सकती है। न तो इसकी कोई आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त योग्यता और अनुभव उपलब्ध है और न ही योग्यता में छूट देना समीचीन होगा क्योंकि उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त के रूप में उम्मीदवार के पास शैक्षिक योग्यता होना आवश्यक है।

(14) प्रतिवादी संख्या 4 के वकील का तर्क कि एक अलग कैडर बनाया गया है, आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा समर्थित नहीं है, जिन्होंने नियम 7 परिशिष्ट "बी" पर भरोसा किया है जो दर्शाता है कि सहायक निदेशक का पद एक कैडर है पद और 50% पदोन्नति से और 50% सीधी भर्ती से भरा जाना है। इसलिए, हमें प्रतिवादी संख्या 4 के उपरोक्त रुख में कोई तथ्य नहीं मिला। प्रतिवादी संख्या 5 में जोड़ा गया, प्रतिवादी ने भी पात्र होने का दावा किया है।

(15) उपर्युक्त कारणों से यह याचिका सफल होती है। सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी क्रमांक 4 को दी गई छूट को नजरअंदाज कर नियमों के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करके पूरे मामले पर पुनर्विचार करें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। यदि

याचिकाकर्ता या अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 5 या अपेक्षित योग्यता वाला कोई अन्य उम्मीदवार उपयुक्त पाया जाता है तो उन्हें सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) के पद पर प्रतिवादी संख्या 4 को पदोन्नति दिए जाने की तिथि से पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति पर ऐसा चयनित उम्मीदवार बकाया वेतन को छोड़कर अन्य सभी परिणामी लाभों के साथ उसी तारीख को देकर पूर्व दिनांकित नियुक्ति का हकदार होगा जो प्रतिवादी संख्या 4 को दी गई थी।

आर.एन.आर.

(1) (1998)6 एस.सी.सी. 165
(2) (2001) 8 एस.सी.सी. 532
(3) एआईआर 1984 एस.सी. 221

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy